नवल टाइम्स

RNI No. UTTHIN/2012/42590

भारत सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

वर्ष : 14 अंकः 21 हिन्दी साप्ताहिक हरिद्वार, बृहस्पतिवार 12 जून 2025 मूल्यः 1 रूपया पृष्ठः 4

धामी कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून(नवल टाइम्स)। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास शामिल हैं। बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामले में कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई। वहीं, हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों को सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी राज्य अनुदानित संस्था उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के संशोधित विभागीय संरचना/ढांचे के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् के गठन के पश्चात् न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर पूर्व में परिषद् के हल्दी, पंतनगर स्थित मुख्यालय हेतु 34 पद एवं एडवांस सेन्टर फॉर कम्प्यूटेशनल एण्ड एप्लाईड बॉयोटेक्नोलॉजी, देहरादून हेतु 12 पद सहित कुल 46 पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परिषद् के स्वीकृत विभागीय संरचना/ढांचे में पदों की संख्या में परिवर्तन किए बिना विभागीय संरचना/ढांचे में मुख्यालय एवं देहरादून सेन्टर/अन्य सेन्टर हेतु समस्त पदों को एकीकृत (एकल संवर्ग) रूप में रखे जाने एवं भर्ती के स्रोत में परिवर्तन किये जाने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देशों के समादर में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के ढांचे में विभागीय आवश्यकतानुसार पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता कराये जाने हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी त्र। इस प्रकार से कुल 18 पदों को बढ़ाया गया है।

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के प्राविधानानुसार जनपद देहरादून के तहसील सदर एवं विकासनगर के अंतर्गत आसन नदी के प्रारम्भिक बिन्दु भट्टा फॉल से आसन बैराज (कुल लगभग 53.00 किमी0 लम्बाई) तक आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या: 477/2022 राजेन्द्र गंगसारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक: 19.03.2024 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की व्यवस्था हेतु अधिनियमित उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के तहसील सदर एवं विकासनगर के अंतर्गत आसन नदी के प्रारम्भिक बिन्दु भट्टा फॉल से आसन बैराज (कुल लगभग 53.00 किमी0 लम्बाई) तक आसन नदी के दोनों तटों पर चिन्हित भूमि को प्रतिषिद्ध तथा निर्बन्धित क्षेत्रों के सम्बन्ध में जारी अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1141, दिनांक: 19.11.2024 के क्रम में अन्तिम अधिसूचना निर्गत किये जाने एवं राज्य की विभिन्न नदियों के बाढ मैदान परिक्षेत्रण हेतु पूर्व में निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लिखित प्रतिषिद्ध तथा निर्बन्धित क्षेत्रों में अंकित अनुमन्य कार्यों में एस0टी0पी0 का निर्माण, रोपवे टावरों का निर्माण, मोबाइल टावर का निर्माण, हाई टेंशन विद्युत ट्रॉन्समिशन हेतु टावर का निर्माण कार्य तथा ऐलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन दिया गया। लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के चयनित 05 निरीक्षण भवनो का पी0पी0पी0 माध्यम से संचालन द्वारा मुद्रीकरण किये जाने का कार्य यू0आई0आई0डी0बी को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित विभिन्न निरीक्षण भवनों/गेस्ट हाउस में से प्रथम चरण के अन्तर्गत 05 चयनित निरीक्षण भवनों (रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल व ऋषिकेश) को पी0पी0पी0 मोड में संचालित करते हुये उनका मुद्रीकरण का कार्य यू0आई0आई0डी0बी द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया। मुद्रीकरण के फलस्वरूप जंहा लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों का बेहतर रख-रखाव संभव होगा एवं विभाग को अधिक राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा, वहीं उस क्षेत्र मे आने वाले पर्यटको को बेहतर आवासीय सुविधायें प्राप्त होगी।

वर्तमान में राज्य में परा-चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु उत्तराखण्ड पराचिकित्सा अधिनियम, 2009 एवं परा-चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी के प्राविधान प्रभावी हैं, के अन्तर्गत विभिन्न 22 पराचिकित्सा विधाओं में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जाता है। देश में सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायियों हेतु शिक्षा और सेवाओं के मानकों को विनियमित करने, आचार संहिता, प्रवेश परीक्षाएं, पाठ्यक्रम मानकीकरण, पंजीकरण के मानकों में एकरूपता लाने, अन्तर्राज्यीय पंजीकरण को सरल एवं सुलभ बनाये जाने तथा कुल 10 श्रेणियों में समूहीकृत 56 व्यवसायी उपाधियों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम-2021 के अध्याय-3 की धारा 22 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद् का गठन करने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फण्ड) सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त विदेशी मदिरा/बियर पर उपकर (सैस) की धनराशि को कॉर्पस फण्ड के रूप में विभागान्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के माध्यम से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के प्राप्त अंतरालों को भरा जायेगा व आवश्यकता एवं प्रस्थिति के अनुसार नवाचार योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जायेगा। प्रमुख रूप से उक्त निधि के तहत आपदा/दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, निराश्रित महिलाओं के जीविकोपार्जन व वृद्ध महिलाओं के लिए जीवन निर्वहन की समुचित व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा।

तीन और मरीजों में कोरोना की पुष्टि, दून में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 38

देहरादून। कोरोना वायरस के तीन और मामले सामने आने के बाद देहरादून जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ते देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। बीते रोज देहरादून जिले के विकासनगर की रहने वाली 20 वर्षीय गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है।

देहरादून के कोविड नोडल अधिकारी डॉ चंदन सिंह ने बताया कि गर्भवती होने के कारण महिला अपना रूटीन चेकअप कराने अस्पताल गई थी। अस्पताल में महिला की कोरोना जांच की गई, तो वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। वह सुभारती अस्पताल में भर्ती है।

इसी तरह सहसपुर मेन बाजार का रहने वाला 45 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉ सीएस रावत ने बताया कि खांसी जुकाम बुखार जैसे लक्षण मिलने पर व्यक्ति ने जांच कराई, तो उसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तीसरा मामला जलवायु विहार टावर का है। यहां 41 वर्षीय महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह महिला होम आइसोलेशन में है और उसमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। स्वास्थ्य महकमे के कोविड नोडल अधिकारी का कहना है कि जिले में लगातार कोविड जांच कराई जा रही है। सभी अस्पतालों में संक्रमितों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना संक्रमण की दिशा में स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है।

इसके अलावा सभी अस्पतालों में जुखाम, बुखार खांसी के लक्षण वाले मरीजों को अलग फ्लू ओपीडी में देखा जा रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट इतना घातक नहीं है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है।

सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: सीएम धामी

देहरादून(सू.वि.)। राज्य हेतु अगले 10 वर्षों के लिए हैली सेवाओं की कार्ययोजना बनाएगी यूकाडा सीएम धामी ने उत्तराखण्ड में सेवाएं दे रहे सभी हैली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स को कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि हैली सेवाओं के सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नही किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर कहा कि हैली सेवा लेने वाले यात्रियों की अधिकाधिक आंकड़ों से आत्ममुग्ध हुए बिना सुरक्षा मानकों को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गत वर्षों में हुए हैली दुर्घटनाओं की आडिट व निरन्तर समीक्षा के भी निर्देश दिए है ताकि इनकी पुनरावृति ना हो।

उन्होंने कहा कि राज्य के नोडल के रूप में यात्रियों की सुरक्षा हमारा का सबसे बड़ा दायित्व हैं। सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी ने हैलीकॉप्टर के नियमित फिटनेस जांच का सख्ती से पालन, हैलीकॉप्टर टिकट बुकिंग हेतु ठोस व प्रभावी एसओपी बनाने एवं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले हैलीकॉप्टर के इंजन के सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने कड़े निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड में अपनी सेवाएं दे

रहे सभी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स तथा ऑपरेटर्स, यूकाडा, एएआईबी एवं डीजीसीए के साथ प्रदेश की हैली सर्विस सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे।

मौसम के कारण हैली सेवाओं में बाधाओं, मौसम की सटीक जानकारी एवं सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री धामी ने केदार वैली के साथ ही अन्य सभी चारधाम वैली में वैदर कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूकाडा को भविष्य में केवल डबल इंजन हैलीकॉप्टर्स संचालित करने हेतु ठोस पॉलिसी तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यूकाडा एवं सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्स को वैष्णो देवी में संचालित की जा रही हैली सर्विस मॉडल का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अत्यधिक अनुभवी पायलटों को ही राज्य में हैली सेवाओं में रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री धामी ने हैली ऑपरेटर्स को यात्रियों के साथ संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने की भी सख्त नसीहत दी है ताकि दुनियाभर से आने वाले पर्यटक देवभूमि से सुखद अनुभव लेकर जाए। उन्होंने हैली ऑपरेटर्स एवं प्रशासन को चारधाम मार्गों पर स्वच्छता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में हैली सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य में बहुत से हैलीपेड निर्माणाधीन हैं। इस वर्ष अभी तक 66000 से अधिक यात्री हैली शटल सेवाओं की सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकाडा को राज्य हेतु अगले 10 वर्षों के लिए हैली सेवाओं की कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी आज की बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं चारधाम राज्य होने के कारण हैली सेवाओं की मांग राज्य में अधिकाधिक बढ़ने वाली है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भविष्य में हैली सेवाओं राज्य का आधार होंगी। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव सोनिका एवं राज्य में सेवाएं दे रहे सभी हैली एवं चार्टर्ड सर्विस ऑपरेटर्स मौजूद थे।

- **हैली सर्विस ऑपरेटर्स को कड़े शब्दों में स्पष्ट किया**
- **हेली सेवा के सुरक्षा मानकों को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश**
- **यूकाडा को भविष्य में केवल डबल इंजन हैलीकॉप्टर्स संचालित करने को ठोस पॉलिसी तैयार करने की जिम्मेदारी दी**

सम्पादकीय

जवाबदेही की कमी पर गंभीर चिन्ता

हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक पुराने न्यायिक आदेश के कारण एफआईआर दर्ज न होने और जस्टिस वर्मा के आवास से बरामद नकदी के मामले पर सवाल उठाए। उपराष्ट्रपति ने न्यायिक समितियों की भूमिका और न्यायिक निर्णयों पर पैसों के संभावित प्रभाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार आज लाचार है क्योंकि एक न्यायिक आदेश एफआईआर दर्ज करने में बाधा बना हुआ है। अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। यह सबसे बुनियादी और शुरुआती कदम है, जो पहले ही दिन उठाया जा सकता था। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि मौजूदा स्थिति में जब तक न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर से अनुमति नहीं मिलती, तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि 'अगर यह अनुमति नहीं दी गई तो क्यों' 'क्या किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव ही इस संकट का समाधान है उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के निवास से बरामद नकदी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की छवि को गहरा आघात देने वाला मामला है। उन्होंने पूछा, अगर यह घटना सामने नहीं आती, तो क्या हमें कभी पता चलता कि और भी ऐसे मामले हो सकते हैं जगदीप धनखड़ ने जोर दिया कि जब नकदी मिलती है तो हमें यह जानना चाहिए कि वह पैसा किसका है, उसकी मनी ट्रेल क्या है, और क्या उस पैसे ने न्यायिक निर्णयों को प्रभावित किया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब जनता का अन्य संस्थाओं से विश्वास उठता है, तब भी वे न्यायपालिका की ओर आशा से देखते हैं। उन्होंने कहा, हमारे न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता और परिश्रम अद्वितीय है लेकिन अगर वहीं संदेह की दृष्टि में आ जाएं तो लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी। यह सोचना कि मीडिया का ध्यान हटते ही मामला ठंडा पड़ जाएगा, एक बहुत बड़ी भूल होगी। इस अपराध के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। धनखड़ ने आगे कहा, मैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। हम ये कह सकते हैं कि नकदी की जब्ती हुई क्योंकि रिपोर्ट कहती है और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक की। हमें लोकतंत्र के विचार को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपनी नैतिकता को इस कदर गिराना नहीं चाहिए। हमें ईमानदारी को समाप्त नहीं करना चाहिए।

बच्चे हर देश के सुनहरे भविष्य की नींव

अनेक कमर्शियल संस्थानों,औद्योगिक संस्थानों, दवा उद्योग,खेत खलियानों गृहउद्योग,इत्यादि अनेक व्यवसायिक क्षेत्रों में छोटे-छोटे बच्चों से श्रम करवाया जाता है,क्योंकि उन क्षेत्रों में कामों के लिए यह छोटे-छोटे बच्चे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और अपेक्षाकृत रोजी या मजदूरी भी इनकी कम होती है, और डेली वेजेस के रूप में रखकर आसानी से अपना काम करवा लेते हैं। दूसरी तरफ हम अनेक चौराहों, बाजारों, हाट बाजारों, में हमने छोटे-छोटे बच्चों को अकेले या अपने मातापिता के साथ खिलौने, खाद्य पदार्थों इत्यादि बेचने को देखते रहते हैं।अनेक बड़ी या छोटी सिटीओ में तो ट्रैफ़िक सिग्नल चौराहों स्टेशनों, बूथों पर अक्सर यह छोटे बच्चे भीख मांगते,सामान बेचते,हमें दिखते रहते हैं। यह नज़ारा हर छोटी बड़ी सिटी के चौराहों पर आसानी से देखने को मिलता है। जबकि संयुक्त राष्ट्र बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करते हुए कहा कि 2025 तक इस प्रथा को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई कीआवश्यकता है। आज इस विषय पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 12 जून 2025 को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2025-बच्चों को मजदूरी नहीं शिक्षा दिलाएं जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक क्षेत्रों का सशक्त उपकरण व रोजगार का अस्त्र है।

बात अगर हम 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लक्ष्य की करें तो,विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जिसे हर साल 12 जून को मनाया जाता है,अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) द्वारा बाल शोषण के गंभीर मुद्दे को उजागर करने और इसे मिटाने के प्रयासों को संगठित करनेके लिए शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह आइएलओ और यूनिसेफ़ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए बाल श्रम पर नए वैश्विक अनुमानों और रुझानों के जारी होने के साथ मेल खाता है। यह महत्वपूर्ण डेटा वैश्विक नीतिगत बहसों का मार्गदर्शन करेगा और सतत विकास लक्ष्य लक्ष्य 8.7 को प्राप्त करनेकी दिशामें प्रयासों को फिर से सक्रिय करेगा।2025 तक सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है।संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, सभी देशों को 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। यह लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 8.7 में शामिल है, जो सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करने का आह्वान करता है।कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशनबाल अधिकारों पर लगातार काम कर रहा है फांडेशन की ओर से बाल मजदूरी पर एक जानकारी दी गई है, इसमें बाल मजदूरी से संबंधित कई जानकारी दी गई है,जनगणना 2011 के डेटा के अनुसार, भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ (10.1 मिलियन) है, इसमें से 0.560 करोड़ (5.6 मिलियन) लड़के और 0.45 करोड़ (4.5 मिलियन) लड़कियां हैं,वहीं हाल के वैश्विक अनुमान के अनुसार 2020 की शुरुआत में वैश्विक स्तरपर 16 करोड़ (160 मिलियन) बच्चे- 6.300 करोड़ (63 मिलियन) लड़कियां और 9.700 करोड़ (97 मिलियन) लड़के - बाल श्रम में थे, जो दुनिया भर में सभी बच्चों में से लगभग 10 में से 1 है,भारत भर में बाल मजदूर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों जैसे ईंट भट्टों, कालीन बुनाई, परिधान निर्माण, घरेलू सेवा, खाद्य भोजनालयों, गन्ना खेतों, मत्स्य पालन और खनन में पाए जा सकते हैं. बच्चों को यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी के उत्पादन सहित कई अन्य प्रकार के शोषण का भी खतरा है।

बांग्लादेश में अप्रैल 2026 तक राष्ट्रीय चुनाव होंगे

नित्य चक्रवर्ती

बांग्लादेश सरकार के अंतरिम मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस ने मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की इस साल दिसंबर में चुनाव कराने की मांग को दरकिनार करते हुए आखिरकार अगले साल अप्रैल के पहले पखवाड़े में देश में राष्ट्रीय चुनाव कराने की घोषणा की है। अंतिम तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जायोगी। चुनाव आयोग चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता के मानदंडों के साथ-साथ मानदंडों को भी अधिसूचित करेगा।

मुख्य सलाहकार डॉ. यूनुस वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर लंदन में हैं। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर और लेबर सरकार के अन्य प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि वह बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात करेंगे। तारिक बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के मुख्य रणनीतिकार हैं। डॉ. यूनुस के साथ उनकी चर्चा आसन्न चुनावों के मद्देनजर खास महत्व रखती है। बांग्लादेश में सभी दल चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि बीएनपी का अभी भी मानना है कि दिसंबर सबसे अच्छा समय है, क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने वार्षिक स्कूली परीक्षाओं, रमजान और उन महीनों के दौरान अचानक तूफान और लगातार बारिश की संभावना के मद्देनजर वह समय सुविधाजनक नहीं हैं। चुनाव आयोग अभ्यावेदन को देखने के बाद तारीखों पर अंतिम फैसला लेगा।

सभी दलों के लिए, अब एक बात तय है कि राष्ट्रीय चुनाव दिसंबर और अप्रैल के बीच कभी भी हो सकते हैं और उन्हें इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। चुनाव आयोग चुनावों में भाग लेने के लिए पात्र दलों की सूची अधिसूचित करेगा, लेकिन रुझान पहले से ही स्पष्ट है। अवामी लीग को छोड़कर, जिसे कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, जमात अल इस्लामी सहित अन्य सभी दल चुनावों में भाग लेने के पात्र हैं। तीस से अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में मुख्य दल बीएनपी, नवगठित नेशनल सिटिज़न्स पार्टी (एनसीपी) और जमात-अल-इस्लामी हैं। अन्य छोटी पार्टियाँ और ढीले-ढाले वामपंथी गठबंधन भी हैं, लेकिन वर्तमान अस्थिर बांग्लादेश में चुनावी दृष्टि से उनका बहुत अधिक प्रभाव नहीं है।

सबसे पहले बीएनपी को लेते हैं। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही बीएनपी संसदीय क्षेत्र में काम कर रही है। बीएनपी की वर्तमान अध्यक्ष खालिदा जिया तीन बार प्रधानमंत्री रहीं। वे चिकित्सा उपचार के लिए देश से बाहर थीं। वे पिछले महीने वापस आईं और अब रणनीति बैठकों की अध्यक्षता कर रही हैं, हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें चुनाव प्रचार का तनाव न लेने के लिए कहा है। इसलिए वे अधिक प्रचार नहीं कर रही हैं, बल्कि लंदन में रहने वाले अपने बेटे तारिक के साथ परामर्श करके स्थानीय नेतृत्व का मार्गदर्शन कर रही हैं। बांग्लादेश की अदालतों में उनके खिलाफ लंबित मामलों का निपटारा होते ही तारिक ढाका वापस लौट आयेंगे। बीएनपी के पास लंबे समय से शासन करने का अनुभव है। पार्टी के नौकरशाहों और बांग्लादेश की सेना के एक बड़े हिस्से से संपर्क हैं। बीएनपी को बांग्लादेश में केंद्र-दक्षिणपंथी पार्टी कहा जा सकता है। पार्टी लचीली है और शीर्ष नेतृत्व भारत जैसे शक्तिशाली पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के महत्व को समझता है। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बीएनपी ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था क्योंकि बीएनपी को लगता था कि भारत अपने हितों की पूर्ति के लिए हसीना का इस्तेमाल कर रहा है और हसीना भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि दे रही हैं ताकि नई दिल्ली उनकी सभी ज्यादतियों को नजरअंदाज कर दे। बीएनपी के नेता अब यह विचार व्यक्त करते हैं कि अगर वे राष्ट्रीय चुनावों के बाद सत्ता में वापस आते हैं तो वे भारत के साथ सामान्य संबंध रखना चाहेंगे।

दूसरी दिखायी देने वाली राजनीतिक पार्टी एनसीपी है। एनसीपी की स्थापना इस साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में हुई थी। अभी तीन महीने से थोड़ा ज्यादा का समय ही बीता है। पार्टी को अभी भी जिलों में गांव स्तर पर अपनी सभी इकाइयां स्थापित करनी हैं। पूरी पार्टी के पास शासन करने का कोई अनुभव नहीं है। उनके अधिकांश शीर्ष नेता भेदभाव विरोधी आंदोलन के अगुआ थे, जिसने पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका था। एनसीपीधर्मनिरपेक्षतावादियों से लेकर कट्टरपंथियों, चीनी समर्थकों से लेकर स्वतंत्रतावादियों तक की विविध ताकतों का एक बेजोड़ मिश्रण है। उनके पास कुछ अनुभवी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता और किसान नेता भी हैं। लेकिन मूल रूप से, एनसीपी का नेतृत्व युवा कट्टरपंथी कर रहे हैं जो सपने देखते हैं और समानता के आधार पर एक नये स्वर्णिम बांग्लादेश के निर्माण की बात करते हैं।

एनसीपी पूरी तरह से भारत विरोधी है। उसके नेतृत्व को लगता है कि अवामी लीग की सभी ज्यादतियों के लिए भारत सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और शेख हसीना के साथ-साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार भी दोषी है। वास्तव में एनसीपी हसीना के कार्यकाल में भारतीय भूमिका का उल्लेख करने में सबसे मुखर थी, जो हसीना विरोधी छात्र आंदोलन का अध्ययन करने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के सामने थी। एनसीपी ने अब चुनाव उद्देश्यों के लिए अपनी कोर समितियों के गठन में तेजी ला दी है।

एनसीपी ज्यादातर कार्यक्रमों में डॉ. यूनुस के साथ है। एनसीपीबीएनपी को अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानती है। सेना की भूमिका पर भी एनसीपी को संदेह है।

जमात अल इस्लामी के मामले में पार्टी के पास बहुत से समर्पित कार्यकर्ता हैं। यूनुस सरकार द्वारा विदेशी चंदे पर प्रतिबंध हटाये जाने के बाद पार्टी के पास अब बहुत सारा धन है। चुनावों में जमात अपने आप में एक नगण्य ताकत है। पहले इसने बीएनपी के साथ गठबंधन किया था और कुछ मान्यता भी हासिल की थी, लेकिन अभी बीएनपी और जमात में टकराव चल रहा है। एनसीपी की तरह ही जमात भी डॉ. यूनुस का समर्थन कर रही है। जमात का एक वर्ग एनसीपी के साथ समझौता चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि एनसीपी का शीर्ष नेतृत्व जमात के साथ किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ है।

डॉ. यूनुस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? यह भी महत्वपूर्ण है। डॉ. यूनुस अब 85 वर्ष के हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि अपने कार्यकाल के दौरान दो बार इस्तीफा देने की धमकी देने के बावजूद नोबेल पुरस्कार विजेता अपने शासकीय समय का आनंद ले रहे हैं। चुनाव के बाद राष्ट्रपति मनोनीत होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव के बाद कौन सा गठबंधन सत्ता में आता है और किस तरह के सौदे होते हैं। एनसीपी और जमात चाहेगी कि डॉ. यूनुस राजनीतिक सुर्खियों में बने रहें, लेकिन क्या बीएनपी इसके लिए राजी होगी?

डॉ. यूनुस के पहले अमेरिकी बाइडेन प्रशासन से संबंध थे, क्योंकि उन्हें क्लिंटन का अच्छा दोस्त माना जाता था। लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप के आने के बाद डॉ. यूनुस का वह महत्व कम हो गया। अब वे 10 मई को युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी प्रशासन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालियादुविधापूर्ण स्थिति का फायदा उठाते हुए ट्रंप के सलाहकारों से नये सिरे से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस परिदृश्य में भारत की स्थिति क्या है? अवामी लीग राष्ट्रीय चुनाव की दौड़ में नहीं है, इसलिए भारत के पास शायद ही कोई ऐसा दल है, जिसमें वह रुचि ले सके। अवामी लीग के संबंध में, नेताओं का कहना है कि वे प्रतिबंध के फैसले को चुनौती देंगे, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि कानून में संशोधन किया जा चुका है। अवामी लीग नेतृत्व भारत की मदद से अपनी भागीदारी से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम है। यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित दो अंतरराष्ट्रीय टीमों ने शेख हसीना शासन पर जुलाई के आंदोलन के दौरान चुनाव धोखाधड़ी और अनावश्यक हत्याओं सहित ज्यादतियों का आरोप लगाते हुए रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

फिलहाल, अवामी लीग नेतृत्व के पास बहुत कम विकल्प हैं। बड़े देशों में, अमेरिका अभी बांग्लादेश में दिलचस्पी नहीं ले रहा है क्योंकि वह अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में बहुत अधिक उलझा हुआ है। चीन अवामी लीग के खिलाफ खड़ा है और वर्तमान में बांग्लादेश शासन के साथ उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। चीन के मित्र बीएनपी और एनसीपी दोनों हैं। ढाका में चीन के राजदूत के पास अब राजनीतिक दलों के अधिकतम आगंतुक आते हैं। बांग्लादेश में कारोबार से कहीं अधिक चीन की महत्वाकांक्षाएं हैं। योजना में बंद पड़े हवाई अड्डों को फिर से चालू करना और चटगांव में नौसैनिक अड्डे को फिर से चालू करना उनमें शामिल है। लेकिन चीन जल्दबाजी में नहीं है। बीजिंग बांग्लादेश में नौकरियां पैदा करने वाली फैक्टरियों का समूह स्थापित करके और फिर भारत को प्रभावित करने वाले अपने भू-राजनीतिक लक्ष्यों के लिए काम करके लोगों का दिल जीतना चाहता है।

भारत में लगातार घटती गरीबी एवं बढ़ती धनाढ्यों की संख्या

वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थान अब यह स्पष्ट रूप से मानने लगे हैं कि विश्व में भारत की आर्थिक ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में जारी किए गए एक सर्वे रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में पिछले बीते वर्ष में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या एवं उनकी संपतियों में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है।

जबकि विश्व के कई देशों विशेष रूप से विकसित देशों में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या एवं इनकी सम्पत्ति में वृद्धि दर लगातार नीचे गिर रही है। इसका आश्य तो अब यही लगाया जा सकता है विश्व में आर्थिक शक्ति अब पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रही है।

भारत में जिस व्यक्ति की शुद्ध सम्पत्ति 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक होती है उसे उच्च नेटवर्थ व्यक्ति (।हङ्खद्ब) कहा जाता है। पिछले वर्ष भारत में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की औसत सम्पत्ति 8.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जबकि विश्व में यह औसतन 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत में मिलिनेयर्स की संख्या बढ़कर 378,810 हो गई है और इनकी कुल सम्पत्ति 1.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्थात 129 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। वर्ष 2024 में भारत में 4,290 अल्ट्रा उच्च नेटवर्थ व्यक्ति निवास कर रहे थे, जिनकी कुल सम्पत्ति 53,477 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी। अल्ट्रा उच्च नेटवर्थ व्यक्ति उस नागरिक को कहते हैं जिसकी शुद्ध सम्पत्ति 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर अथवा उससे अधिक होती है।

भारत में तो उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है परंतु यूरोप में इनकी संख्या 2.1 प्रतिशत घटी है। ब्रिटेन में 14,000, फ्रान्स में 21,000, जर्मनी में 41,000 उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या घटी है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या 1.7 प्रतिशत बढ़ी है तो लेटिन अमेरिका में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या 8.5 प्रतिशत घटी है। साथ ही, मध्य पूर्व में भी उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या में 2.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। क्या भारत में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की बढ़ती संख्या एवं इनकी बढ़ती सम्पत्ति से भारत में कहीं आर्थिक असमानता के गहराने का संकट तो खड़ा नहीं हो रहा है। हालांकि भारत में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की बढ़ती सम्पत्ति, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रतीक भी है। परंतु, यदि इस बढ़ी हुई सम्पत्ति का लाभ समाज के समस्त नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है तो यह सोचनीय प्रशन्न अवश्य है।

राज्यपाल ने किया वीरता पदक विजेताओं एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान

नैनीताल(नवल टाइम्स)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को राजभवन नैनीताल में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ''एक शाम सैनिकों के नाम'' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं और सराहनीय कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अर्धसैनिक बल के जवानों और अधिकारियों को राज्यपाल द्वारा प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। (सूची संलग्न)

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड वीरों की भूमि है, जिसे 'देवभूमि' के साथ-साथ 'वीरभूमि' भी कहा जाता है। यहां अनेक वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का भारतीय सेनाओं में योगदान लगभग 18 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि यह राज्य वास्तव में देश की रक्षा की एक मजबूत रीढ़ है। देश पर बलिदान होने वाले हर पाँचवें सैनिक का उत्तराखण्ड से होना, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि इस राज्य की रगों में दौड़ता राष्ट्र प्रेम है।

उन्होंने कहा कि आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास है। यह हमारे सैनिकों और उनके परिवारों को संदेश देता है कि उनका बलिदान न केवल हमारे लिए अमूल्य है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।

राज्यपाल ने हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और अदम्य साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत अब नई युद्ध प्रणालियों और आधुनिक तकनीकों के साथ पूरी तरह सजग और सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमें अभी इन सभी चुनौमियों के लिए तैयार रहना होगा। इस ऑपरेशन में देश ने अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एकजुटता दिखाई वह प्रशंसनीय है। पूर्व सैनिकों की भूमिका की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनकी सेवा केवल वर्दी तक सीमित नहीं है। समाज में वे आज भी अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति के प्रेरणास्त्रोत हैं। उन्होंने कहा कि देश के पुनर्निर्माण में उनका योगदान अनमोल है और युवाओं के लिए मार्गदर्शक है।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड केवल वीर भूमि ही नहीं, बल्कि संभावनाओं की धरती भी है। प्रकृति ने इस राज्य को जो अपार संपदाएं दी हैं, उनका सतत और सृजनात्मक उपयोग करते हुए राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं से आह्वान किया कि वे होम स्टे, शहद उत्पादन, अरोमा उद्योग और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राज्य की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनें। इससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।

इस अवसर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि उत्तराखण्ड केवल पहाड़ों की धरती नहीं, यह देश की रक्षा करने वाले वीरों की भूमि है, जहाँ हमारे जवानों ने हमेशा अद्वितीय साहस का परिचय दिया है। आज जब इतने अलंकृत वीर सैनिक एक साथ एक मंच पर उपस्थित है, तो यह केवल सम्मान का अवसर नहीं, बल्कि प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बन जाता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की प्रेरणा से राजभवन नैनीताल में पहली बार सैनिकों के सम्मान में यह अभूतपूर्व कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो हमारी प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में उपस्थित सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने विचार रखते हुए सैनिक कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी दी और उपस्थित गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों को भावविभोर कर दिया। कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस अवसर पर प्रथम महिला गुरमीत कौर, जीओसी उत्तर भारत एरिया लेफ्टिनेंट जनरल डी. जी. मिश्रा, लेफ्टिनेंट जनरल जी एस बिष्ट, लेफ्टिनेंट जनरल जी.एस. कटोच, एयर मार्शल के डी सिंह, एसएसपी पी एन मीणा, कुलपति कुमाऊं विवि प्रो दीवान सिंह रावत, निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृत लाल सहित बड़ी संख्या में वीर सैनिक, पूर्व सैनिक, उनके परिवारजन, सैन्य अधिकारीगण, एवं विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित थे।

सम्मानित होने वाले सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों में 11 राष्ट्रीय राइफल्स के कमान अधिकारी कर्नल शीशपाल सिंह, 5वीं गोरखा रेजीमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर सिंह कालाकोटी, पैरा रेजीमेंट के ले0 कर्नल नीतीश त्यागी, ग्रेनेडियर्स रेजीमेंट के ले0 कर्नल खीम सिंह, 666 आर्मी एवीएन एसक्यूएन (आरओ) रेजीमेंट के ले0 कर्नल मोहित रावत, 14 डोगरा रेजीमेंट के मेजर सौरव सिंह, 3 पैरा रेजीमेंट के मेजर अरविंद चंद, 1 लद्दाख स्काउट के मेजर प्रसून पांडे, 19 बीएन मद्रास मेजीमेंट के मेजर राजेश सिंह, 4 गढ़वाल राइफल्स के सुबेदार ललित मोहन सिंह (रि.), 9 पैरा (एसएफ) रेजीमेंट के हवलदार जोगेंद्र सिंह, 9 पैरा रेजीमेंट के लॉन्स नायक संजय बिष्ट (मरणोपरांत) के साथ ही सामाजिक कार्यों के माध्यम से सराहनीय कार्य करने वाले ऑनरेरी सूबेदार मेजर खड़क सिंह कार्की (से.नि.), नायक जगदीश चन्द्र जोशी (से.नि.) को सम्मानित किया।

सम्मानित होने वाले अर्धसैनिक बल जवानों में एसएसबी के हेड कांस्टेबल मंजीत, कांस्टेबल श्याम सिंह मेर और कांस्टेबल संदीप कुमार के अलावा आईटीबीपी के कांस्टेबल मनीषा और कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह को सम्मानित किया। कार्यक्रम में 7वीं बटालियन असम रेजिमेंट और 418 फील्ड कंपनी इंजीनियर्स को भी उनके सराहनीय योगदान के लिए यूनिट प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।

सैनिक सम्मेलन में एसएसपी ने किया पुलिसकर्मियों को सम्मानित

○ 34 जवान मैन आफ द मंथ और 4 महिला पुलिसकर्मी चुनी गयी वुमेन आफ द मंथ

○ एलआईयू के अपर उपनिरीक्षक चन्द्रसिंह पंवार और मुख्य आरक्षी मंशाराम भी हुए सम्मानित

हरिद्वार(नवल टाइम्स)। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने 34 पुलिस जवानों को मैन आफ द मंथ और 4 महिला आरक्षियों को वूमेन आफ द मंथ सम्मान से सम्मानित किया है। रोशनाबाद स्थित जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित सैनिक सम्मेलन के दौरान मई माह में विभिन्न प्रकरणों के अनावरण में योगदान, लगन से ड्यूटी करने और मानवीय कार्यों के आधार पर चयनित किए गए पुलिस जवानों की भूमिका की सराहना करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने सभी से जनपद को अपराध मुक्त करने एवं पुलिस की छवि को स्वच्छ बनाने के लिए सभी से सहयोग मांगा तथा श्रद्धालुओं एवं सभ्य पर्यटकों से अच्छा व्यवहार करने की सीख दी।

पुलिस कप्तान ने कहा कि आप विभाग की रीढ़ हैं। अपना महत्व समझें और उसी के मुताबिक कड़ी मेहनत कर औरों के लिए आदर्श बनें।

एसएसपी ने पुलिस लाइन रोशनाबाद में तैनात सफाई वीर महिपाल सैनी की मेहनत की प्रशंसा करते हुए उन्हे भी सम्मानित किया। इस दौरान अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी महिपाल सैनी के कार्यों की सराहना की। कोतवाली नगर के एसआई चरण सिंह, एसआई संजीत कण्डारी, कांस्टेबल निर्मल, कांस्टेबल सुनील चौहान, होमगार्ड अनुज कुमार थाना श्यामपुर, हेड कांस्टेबल रविन्द्र तोमर, कांस्टेबल विशन सिंह चौहान थाना कनखल, कांस्टेबल अधीप कुमार आईआरबी प्रथम, कांस्टबल सुखदेव कोतवाली ज्वालापुर, कांस्टेबल जयपाल सिंह थाना बहादराबाद, कांस्टेबल अर्जुन, कांस्टेबल विवेक गुंसाई कोतवाली रानीपुर, एसआई नरेंद्र सिंह थाना सिडकुल, कांस्टेबल प्रदीप भंडारी कोतवाली रूड़की, अपर उपनिरीक्षक पुष्कर सिंह चौहान थाना कलियर, एसएसआई अजय शाह, कांस्टेबल रणवीर सिंह कोतवाली गंगनहर, एसआई हेमदत्त भारद्वाज कोतवाली मंगलौर, हेडकांस्टेबल गीतम सिंह थाना भगवानपुर, हेडकांस्टेबल रामवीर थाना झबरेड़ा, हेडकांस्टेबल दिनेश चन्द्र कोतवाली लकसर, एसएसआई यशवीर सिंह नेगी, कांस्टेबल राकेश नेगी थाना पथरी, एसआई अशोक सिरसवाल, कांस्टेबल ऋतिक कुमार थाना खानपुर, महिला कांस्टेबल नीलम चौहान थाना बुग्गावाला, कांस्टेबल सियाराम एसपी ग्रामीण कार्यालय, महिला हेडकांस्टेबल उषा सिरोहा सीओ ज्वालापुर कार्यालय, सफाईकर्मी महिपाल सिंह पुलिस लाईन हरिद्वार, कांस्टेबल संजय कुमार सीपीयू रूड़की, महिला होमगार्ड रेखा रतूड़ी यातायात पुलिस हरिद्वार, फायर मैन खजान सिंह राणा फायर स्टेशन मायापुर, महिला कांस्टेबल पूनम मनराल दूरसंचार, हेडकांस्टेबल अश्वनी कुमार सीआईयू रूड़की, हेडकांस्टेबल नीरज रावत, अपर उपनिरीक्षक चन्द्रसिंह पंवार, मुख्य आरक्षी मंशाराम एलआईयू, प्रधान लिपिक कांस्टेबल प्रदीप भट्ट।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का टीकाकरण पर फोकस, 2026 तक उत्तराखंड बनेगा एम.आर. फ्री राज्य

देहरादून। उत्तराखंड में खसरा और रूबेला जैसी अत्यधिक संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन तथा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से आज राज्य टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड के सभागार में सम्पन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वाति एस. भदौरिया, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड ने की। बैठक में वर्ष 2026 तक उत्तराखंड को खसरा-रूबेला मुक्त बनाने की दिशा में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। मिशन निदेशक ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

बैठक में जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई उनमें सर्विलांस के माध्यम से खसरा व रूबेला के मामलों की सक्रिय पहचान, प्रयोगशाला से पुष्टि एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना। प्रकोप की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करना। पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण सत्रों की डिजिटल मॉनिटरिंग और विश्लेषण। जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से समुदायों को टीकाकरण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना।

स्वाति एस. भदौरिया ने बताया कि खसरा और रूबेला दोनों ही संक्रामक वायरल बीमारियां हैं, जो विशेषकर बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। ये बीमारियां निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर, अंधत्व और यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बन सकती हैं। गर्भवती महिलाओं में ये भ्रूण विकृति और गर्भपात जैसी जटिलताओं को जन्म देती हैं। इसलिए इनका उन्मूलन वैश्विक जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड में इस दिशा में 95 प्रतिशत या उससे अधिक टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सामुदायिक प्रतिरक्षा विकसित की जा सके।मिशन निदेशक ने जानकारी दी कि जुलाई 2025 से अगले तीन महीनों तक पूरे प्रदेश में विशेष एम.आर. टीकाकरण सप्ताह आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों की निगरानी यूडब्लयूआईएन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यदि किसी कारणवश कोई टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं हो पाता है, तो उसके पीछे के कारणों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।बैठक में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र में टीकाकरण सत्रों की नियमित समीक्षा, जन-जागरूकता गतिविधियों और सत्र आयोजन पर विशेष ध्यान दें।

विकसित भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं: सीएम धामी

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अलग पहचान बनाई है। विकसित भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ कार्य किये जा रहे हैं। यह कालखंड हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। विकास और नवाचार की दिशा में देश में अनेक कार्य हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरदान साबित हो रही है। मेक इन इंडिया की ताकत से निर्यात के क्षेत्र में भारत की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-धन योजना, उज्जवला योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता अभियान, किसान सम्मान निधि और निशुल्क राशन योजना जैसी अनेकों जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज भारत की गरीबी दर में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। पिछले 11 साल में 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 की समाप्ति, तीन तलाक पर प्रतिबंध जैसे साहसिक निर्णय लिये गये। उन्होंने कहा कि भारत न केवल स्वदेशी रक्षा उपकरण बना रहा है, बल्कि दुनिया को निर्यात भी कर रहा है। भारत के रक्षा निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स से छूट दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को एक नई रफ्तार दी है। 99 प्रतिशत गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी का भी तेजी से विस्तार हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्टार्टअप इंडिया योजना ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड पर भी तेजी से कार्य हो रहे हैं। केदारनाथ और हेमकुंट साहिब रोपवे निर्माण के बाद श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी

पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने राज्यपाल से की भेंट

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से मंगलवार को राजभवन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने शिष्टाचार भेंट की।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मंत्री गणेश जोशी ने की भेंट

देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान, मंत्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को गंगाजलि और उत्तराखण्ड के पारंपरिक औद्योनिक उत्पाद भेंट की। मुलाकात के दौरान राज्य में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने और नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा

कृषि मंत्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसे मसूरी और नैनीताल पर पर्यटकों का अत्यधिक दबाव है। उन्होंने इस समस्या को कम करने और पर्यटकों को अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए इन स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। जिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया।

केंद्र सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

हरिद्वार(नवल टाइम्स)। भारतीय जनता पार्टी जिला हरिद्वार द्वारा केंद्र सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने पर होटल मधुबन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें सर्वप्रथम मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां बताई। तत्पश्चात सरकार की उपलब्धियो की प्रदर्शनी लगाई गई जिसका उद्घाटन आए हुए अतिथियों ने किया। जिला प्रोफेशनल मीट में अपने स्वागत संबोधन में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृत काल में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है मोदी सरकार की हर योजना में केंद्र और जनकल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ-साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है।

वक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री व हरिद्वार जिला प्रभारी आदित्य चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है।

Ncsc जैसे संस्थानों की स्थापना ने देश के महत्वपूर्ण ढांचों को साइबर हमलों से सुरक्षित किया है। आकाश ब्रह्मोस और अग्नि जैसे मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की बढ़ती सामरिक ताकत और रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रमाण है राफेल विमान के आगमन और एस-400 प्रणाली की तैनाती से भारत की वायु सुरक्षा अजेय बनी है यह एक ऐसा भारत है जो न केवल सीमाओं की रक्षा कर सकता है बल्कि शांति बनाए रखने के लिए भी सक्षम शक्ति के रूप में भी खड़ा है।भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी का यह भारत शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है।

मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए प्रदेश में 1000 से अधिक नए बूथ होंगे स्थापित

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशों के क्रम में बुधवार को सचिवालय में मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं, सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने को किए जा रहे प्रयासों सहित अन्य सुधारात्मक पहलों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल में ही मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। वहीं प्रदेश में नई पहल करते हुए मतदाता जागरूकता के लिए भी स्वीप गतिविधियों के माध्यम से माहवार अलग-अलग थीम पर कार्य किया जा रहा है। डॉ पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से 1200 तक सीमित कर दी गई है। जिससे प्रदेश में लगभग 1 हजार से अधिक नए बूथ स्थापित किए जाएंगे। बताया कि नए बूथ स्थापित होने से मतदाताओं को और सुविधा होगी। बूथ पर लंबी लाइन नहीं लगेंगी और मतदाताओं के घर के समीप ही बूथ उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि आयोग के नए दिशा निर्देशों के अनुसार ऊंची इमारतों/कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे। मतदाता सूची अपडेशन के लिए, मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे आरजीआई डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन के बाद अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पर मोबाइल डिपॉजिट केंद्र की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटर इनफार्मेशन स्लिप को अधिक मतदाता अनुकूल बनाया जाएगा। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया की मान्यता प्राप्त दलों के साथ उत्तराखंड में अब तक 85 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सीईओ स्तर पर 2, डीईओ स्तर पर 13 और ईआरओ स्तर पर 70 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गई हैं। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा नई दिल्ली में बूथ लेवल ऑफिसरों का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किया जा रहा है।

कानूनी सलाहकार
एड. अनुज कुमार शर्मा
चैम्बर नं. 20, रोशनाबाद
हरिद्वार (उत्तराखंड)
मो. 9837387718

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजीव शर्मा ने किरण ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, निकट गुरूकुल कांगड़ी फार्मेसी, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखंड) से छपवाकर, म.नं. डी-31/2 आदर्शनगर कालोनी, गोल गुरूद्वारा, सेंटमेरी स्कूल के पीछे, ज्वालापुर हरिद्वार (उत्तराखंड) से प्रकाशित किया।

: सम्पादक :
संजीव शर्मा
मो. 8057605991/9897106991
ईमेल: navaltimes@gmail.com
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार होगा

प्रबंध संपादक
डा. संदीप भारद्वाज
बिजनौर प्रभारी
विशाल शर्मा

सभी पद अवैतनिक हैं